प्रकाशनार्थ आलेख

राश्ट्रपति जी! छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा ही रहने दो

जनकलाल ठाकुर

छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष आप आए थे। आपकी 2020 तक भारत को विकसित बनाने की परिकल्पना को देश भर में अमली जामा पहनाया जा रहा है। इस अभियान का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी होना है। इसका चित्रण आपके व्याख्यान में भी था कि 'रतनजोत से बायो–डीजल उत्पादन में यह राज्य जहां अग्रणी होगा, वहीं भविष्य में 'डायमंड स्टेट' भी कहलाएगा''। आप छत्तीसगढ़ को 'रतनजोत' के प्रदेश के रूप में विकास देखना चाहते हैं। पर माननीय राष्ट्रपति जी! महलों में रहने वाले नए राजाओं, कारिंदों के बीच छत्तीसगढ़ की जमीनी सच्चाई को आप नहीं देख सके और लाऊडस्पीकर पर नेताओं द्वारा सजाए गए नारों के शोरगुल में न ही 2 करोड़ 14 लाख छत्तीसगढ़वासियों की आवाज सुन सके, जो उस समय खेतों में अपने पसीने से पैदा की गई धान की फसल को काटने में मशगूल थे। इसलिए आप एक ओर तो छत्तीसगढ़ की असली पहचान से रूबरू होने से पूरी तौर पर विफल रहे, जो 'धान का कटोरा' के नाम से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है।

जब से खेती–किसानी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है, तब से लेकर आज तक कोई 1,50,000 धान की प्रजातियां यहां के किसानों ने खुद खोजीं और विकसित की हैं। लेकिन अधिकांश प्रजातियां आधुनिक खेती के नाम पर और 'हरित क्रांति' के नारे में संकर (तथाकथित उन्नत) किस्मों के बीजों के इस्तेमाल से या तो विलोपित हो गईं या रासायनिक खाद और कीटनाशक के चलते नष्ट हो गईं। बावजूद इसके आज भी 22,972 धान की किस्में छत्तीसगढ़ में बची हुई हैं। आपको यह बताते हुए भी हमें गर्व हो रहा है कि हमारे पूर्वजों ने धान की लाखों प्रजातियां अपने परंपरागत ज्ञान और मेहनत के बलबूते पर तब पैदा की थीं, जब अमरीका का जन्म ही नहीं हुआ था और न ही इन तथाकथित आधुनिक देशों में 'कृषि विज्ञान' नाम की कोई चीज थी।

आप जानते ही होंगे कि छत्तीसगढ़ में हर साल औसतन 60 लाख टन चावल पैदा होता है। वह भी तब, मात्र 16 प्रतिशत खेती योग्य भूमि में ही सिंचाई की व्यवस्था है। इसका हिसाब यह हुआ कि यदि इस धान को छत्तीसगढ़ की जनता के बीच बराबर–बराबर बांट दिया जाए तो हर नागरिक के हिस्से में 2 क्विंटल 80 किलो चावल मिलेगा, जिसे वह 560 दिन यानी कि डेढ़ साल तक खा सकती है।

छत्तीसगढ़ का धान–चावल यहां की अर्थव्यवस्था की ही आधारशिला नहीं है, वरन इसकी सांस्कृतिक पहचान और अस्मिता का अभिन्न अंग भी है। जब हम किसी को तिलक लगाते हैं तो 'चावल' का ही इस्तेमाल करते हैं। यहां कोई भी पूजा 'चावल' के बिना नहीं होती;तमाम त्यौहारों का संबंध 'धान–चावल' से ही है, जैसे कि 'छेर–छेरा' और 'अक्ति' त्यौहार आदि। इस स्थिति में माननीय राष्ट्रपति जी, आपका छत्तीसगढ़ को 'रतनजोत की धरती' की संज्ञा देना करोंड़ों छत्तीसगढ़वासियों का न केवल अपमान है; वरन उनके जीने के अधिकार और जीविकोपार्जन के मूल संसाधन पर एक कुठाराघात है, जिसे छत्तीसगढ़ की देशप्रेमी और ईमानदार जनता कबूल नहीं करेगी।

दरअसल 'रतनजोत की राजनीति' छत्तीसगढ़ में 'भोजन सम्प्रभुता' के विनाश का रास्ता चुनकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ को विदेशी गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की एक सोची–समझी साजिश है। आप जैसे विद्वान वैज्ञानिक को इतिहास के पन्नो की ओर ले जाते हुए याद दिलाना चाहेंगे कि 'भोजन की राजनीति' का पर्दाफाश अमरीकी कांग्रेस के एक गुप्त दस्तावेज से 60 वें दशक में ही हो चुका था, जब यह उजागर हुआ कि भविष्य में अन्य राष्ट्रों और खासकर विकासशील देशों को अपने आधीन रखने की साम्राज्यवादी साजिश मे भोजन सबसे ताकतवर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए न कि बंदूक और बम। आज यह सच साबित हो रहा है कि भूमंडलीकरण के युग में 'विश्व व्यापार संगठन' के तहत पूरी दुनिया में, खासकर भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, खेती किसानी को नष्ट करने के लिए अमरीका के मार्गदर्शन मे तैयार किए गए कृषि विकास के प्रारूप को छत्तीसगढ़ जैसे 'धान के कटोरा' पर थोपा जा रहा है, जिसमें रतनजोत की खेती शुरु कराना यानी स्थानीय धान की खेती को नष्ट करना उसी 'भोजन–हथियार' का एक अभिन्न अंग है।

दरअसल 'रतनजोत की राजनीति' के पीछे 'भोजन सम्प्रभुता' को समाप्त कर 'धान का कटोरा' को 'भूख का कटोरा' में बदल देने की एक साजिश है; जिसके पीछे बहुराष्ट्रीय शक्तियों का हाथ है। धान के दुर्लभ बीजों पर 'सिजेंटा' और 'महको–मोन्सांटों' नामक विदेशी कंपनियों के हमले से यह उजागर भी होता है। आप यह जो जानते ही होंगे कि रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में संग्रहीत धान के जर्म–प्लाज्म से हाईब्रिड किस्में तैयार करने हेतु 'सिजेंटा' बहुराष्ट्रीय कंपनी से एक गुप्त समझौता कर लिया था, जिसे आंदोलन के चलते रद्द करना पड़ा। इसी प्रकार 'महकों–मोंसाटों नामक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा 'बी. टी. चावल' बी.टी. भिंडी' बी.टी. बैगन' के खतरनाक प्रयोग रायपुर कृषि विश्वविद्यालय की सांठ–गांठ से किए जा रहे हैं, इस खतरनाक प्रयोग का पता चलने पर छत्तीसगढ़ के नागरिकों में, खासकर किसानों मे, काफी रोष व्याप्त है। छत्तीसगढ़ राज्य के विकास का प्रारूप, जिसे 'विजन–2010' नामक दस्तावेज कहा गया है। इसमें 'धान का कटोरा' शब्द का कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है। यह दस्तावेज एक बहुराष्ट्रीय कंपनी 'प्राइस वाटर हाउस कूपर्स' ने तैयार किया है।

इसके अलावा 'रतनजोत की राजनीति' के तहत छत्तीसगढ़ में वनभूमि और सार्वजनिक जगहों मे रतनजोत की खेती कर लगभग 3,50,000 आदिवासियों को उनके पूर्वजों के जंगलों और जमीनों से बेदखल कर उजाड़ दिया जाएगा। रतनजोत के जहरीले खतरों से अभी से ही जन–जीवन प्रभावित हो रहा है। 22

नवंबर 2006 को छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के मगरलोड में रतनजोत के फल खाकर कोई 16 बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। राष्ट्रपति महोदय, एक वैज्ञानिक होने के नाते आप अवश्य ही यह जानते होंगे कि रतनजोत के फल इतने जहरीले होते हैं कि इनसे कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। लेकिन मीठे होने के कारण बच्चे और पशु इसे खाने को लालायित रहते हैं।

इस दिग्भ्रमित व विनाशकारी विकास की अवधारणा को दुरुस्तकर सही दिशा व दृष्टि देने के लिए जमीनी सच्चाई को पहचानें, कोई भी लक्ष्य 'सत्य' और 'अर्थ' पर आधारित हो, हम छत्तीसगढ़ के देशप्रेमी नागरिक आपसे यही आग्रह करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे दिलों में कोई सपना नहीं है। हम 'नए भारत के लिए नए छत्तीसगढ़' का निर्माण करने के लिए संकल्परत् हैं, एक ऐसा राज्य जिसकी आधारशिला 'धान का कटोरा' के मूल्यों पर आधारित होगी जैसे कि न्याय, शांति, समानता और मानव गरिमा आदि।

शब्द संख्या– 1035,

आलेख प्रकाशित होने की स्थिति में अखबार की कतरन और पारिश्रमिक राशि 'पीपुल्स न्यूज नेटवर्क' दिल्ली के पते पर भेजें।

पीपुल्स न्यूज नेटवर्क (समाचार–विचार सर्विस) संपादक मंडल– अमित सेन गुप्ता, अरुण अग्रवाल, भारत डोगरा, ई पी मेनन, हर्ष डोभाल, जावेद नकवी, प्रशांत भूषण, संजय काक

कार्यकारी सम्पादक –शिराज केसर, पीएनएन, 14 सुप्रीम एन्क्लेव, मयूर विहार फेज 1, दिल्ली–91, फोन–011,22756796 ईमेल–peoplesnewsnetwork@gmail.com

पारिश्रमिक राशि 'पीपुल्स न्यूज नूटवर्क' के नाम भेजें।

सम्पर्क– शिराज केसर, 14 सुप्रीम एंक्लेव, मयूर विहार फेज 1, दिल्ली–91, 011–22756796